an>

Title: Need to provide remunerative price of potato to farmers in the country.

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर-सीकरी)ः वर्तमान में आलू की गिरती कीमतों का आप संदर्भ गृहण करें। आज आलू किसान को अपनी आलू की फसल का बाजार में कोई भी खरीदार नहीं है। मजबूर होकर किसानों को आलू 100 रू. क्विंटल में बेचना पड़ रहा है या फिर कोल्ड स्टोरों में मजबूरन रखा जा रहा है। कोल्ड स्टोरों का भाड़ा अलग से किसानों को देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में किसानों की लागत मूल्य करीबन 600 रू. क्विंटल आती है, फसल से नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसानों की स्थिति मजबूरन आत्महत्याएँ करने को हो गई है और कई आत्महत्याएँ हो भी चुकी हैं।

2014 चुनावों (लोकसभा) में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य देंगे और वह आज आलू किसानों को नहीं मिल रहा है।

आलू के चिप्स बाजार में करीब 400-500 रू. किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और किसानों का आलू मात्र 100 रू. क्विंटल बिक रहा है, कितनी असमानता है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसानों के लिए किसान आयोग का गठन करना अनिवार्य है जिससे यह आयोग हर फसल का सही आंकलन करके मूल्य निर्धारित करें और इस आयोग में एक किसान परिवार से सदस्य बनवाया जाए जिससे सुझाव दे सके।

1. आलू किसान का समर्थन मूल्य करीब 700-800 रूपए क्विंटल रखा जाए।

2. आलू की फसल को सरकारी खरीद के तहत खरीदा जाए।

3. आगरा में आलू की प्रोसेसिंग यूनिटें लगवायी जाए जिससे आलू की खपत हो सके।

4. आगरा में आलू का निर्यात केन्द्र खोले जाए जिससे आलू को विदेशों में भेजा जा सके।

अगर किसानों की आलू फसल पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आलू किसान बिल्कुल मर जायेगा जिसका बुरा असर सरकार पर पड़ेगा।